

**इस्पात के मूल्यों में वृद्धि**

1043. श्री राम जेटमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

श्री राम नरेश यादव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि संयुक्त संघर्ष समिति का भी यही विचार है कि मूल्य बढ़ाए जाने चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे लौह के मूल्यों में अभी हाल में ही वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं तो किन कारणों से इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने को आवश्यक समझा जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने की अपेक्षा सरकारी करों में कुछ रियायत देने का विचार रखती है; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) में (घ) मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित कुछ इस्पात मर्दों के मूल्य संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं ताकि कोयला, बिजली, रेल-भाड़े आदि जैसे आदानों की कीमत में हुई वृद्धि तथा उत्पाद शुल्क जैसी लेवी को निष्प्रभावित किया जा सके। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा लोहे और इस्पात की पिछली मासिक मूल्य वृद्धि जनवरी 1989 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इस्पात बनाने के लिए आदानों के मूल्यों में विभिन्न स्तरों पर वृद्धि हुई है, जो संयुक्त संघर्ष समिति के मतानुसार आवश्यक थी।

(ङ) और (च) इस मामले के बारे में निर्णय लेने से पूर्व सरकार को सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

**गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़ना**

1044. श्री राम नरेश यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी को एक नहर द्वारा गंगा नदी से जोड़ने के संबंध में अपना प्रतिवेदन देने के लिए गठित किए गए अध्ययन दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**Financial Assistance promised by Japanese Prime Minister**

1045. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Japanese Prime Minister has promised financial assistance to India during his talks with the Indian Prime Minister in Delhi recently;

(b) if so what is the amount of aid promised and at what interest: and

(c) what are the terms and conditions for the aid?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) During his recent visit, the Japanese Prime Minister has indicated that Government of Japan would try to extend Yen loans in the region of about Yen 100 billion in the current